(ii) Inadequate raw coal feed to washeries.

(iii) Frequent Power failures.

Major steps taken to augment indigenous availability of coking coal, *inter-alia*, include:-

(i) Increasing raw coking coal availability by reorganising existing mines and development of new mines.

(ii) Modification of the existing coking coal washeries to improve the capacity utilisation as well as the quality of washed coking coal.

(iii) Increasing raw coal feed to washeries by supplying low volatile medium coking coals of suitable quality.

(iv) Early commissioning of two new washeries under construction at Madhuband (BCCL) and Kedla (CCL) for increasing the existing washing capacity.

(d) Details of washery-wise production of coal and their capacity utilisation (1992-93 to 94-95).

Washery	Washed coal production (mt)			Capacity Utilisation (%)		
	1994-95	93-94	92-93	1994-95	93-94	92-93
Durga I & II	1.11	1.14	1.03	61.53	62.80	58.90
Bhojudih	1.01	0.98	0.94	92.66	88.40	87.60
Patherdin	0.62	0.52	0.51	62.67	61.80	59.40
Lodna	0.19	0.20	0.19	85.10	87.50	57.50
Sudamdih	0.46	0.34	0.43	50.90	40.50	43.00
Borora	0.13	0.12	0.13	81.48	78.60	66.70
Moonidih	0.54	0.51	0.46	53.93	52.30	45.50
Mohuda	0.24	0.26	0.28	52.92	57.10	63.50
Kargali	1.05	1.35	1.39	80.77	91.20	93.00
Kathara	0.78	0.82	0.88	58.17	60.70	64.00
Swang	0.60	0.70	0.69	130.93	131.90	141.30
Gidi	0.92	0.96	0.95	85.90	89.50	88.00
Rajrappa	0.90	0.97	1.01	56.63	56.80	58.00
Nandan WCL	0.39	0.37	0.37	57.08	51.40	50.50

गुजरात की विद्युत परियोजनाओं द्वारा कोयले की मांग

*12. **श्री राजूभाई ए॰ परमार:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अपनी प्रमुख विद्युत परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए कोयले की आपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की खपत की उसकी वार्षिक मांग कितनी है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की मांग राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं होती है। इसका मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा अनुमोदित समग्र रूप में क्षेत्रीय आंकड़ों के अंदर ही किया जाता है। तदनुसार गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के 4 तापीय विद्युत गृहों की वर्ष 1995-96 के लिए मांग का 12.19 मिलियन टन मूल्यांकन किया गया है।

कोयला कंपनी गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के स्वामित्वाधीन विद्युत गृहों को इस गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में पुरजोर प्रयास कर रही है, जोकि उत्पादन, परिवहन, कोयले की आपूर्ति के लिए

समय पर अदायगी किए जाने, और यह भी विद्युत गृहों पर उचित रूप में उतराई किए जाने संबंधी व्यवस्था किए जाने संबंधी अवरोधों के अधीन है। वास्तव में, विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति तथा संचलन किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें गुजरात में स्थित विद्युत गृह भी शामिल हैं।

Allocations made for poverty alleviation programmes

*13. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the allocations made to different State during the current financial year for implementing IRDP, JRY, PMRY and other poverty alleviation programmes;

(b) the target fixed for implementing these programmes during the current financial year;

(c) the State-wise expenditure percentage and achievement as on 31st October, 1995; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA) : (a) to (d) Three major Centrally Sponsored Poverty Alleviation Programmes which are being implemented to in the rural areas of the country are: (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and (iii) the Employment Assurance Scheme (EAS). Information available on financial and physical performance under three programmes during the current year is given at Annexure [*See* Appendix 175 Annexure No. 5]

The Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) provides self employment to educated unemployed youth both in rural and urban areas. The scheme has been designed to provide employment by setting up of micro enterprises by the educated unemployed youth. It relates to the setting up of self employment ventures through industry, service and business routes. Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY) which was in operation from 1983-84 to 1993-94 has been subsumed in the PMRY. Information available on State-wise progress under PMRY (1995-96) upto October, 1995 is given at Annexure [*See* Appendix 175 Annexure No. 6]

सब्जियों की बिक्री संबंधी समाचार

*14. श्री राम देव भण्डारी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 1995 के "हिंदुस्तान" के दिल्ली संस्करण में "अब सब्जी को रंग कर बेचा जा रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में कुछ सब्जी की दुकानों पर छापे मारे हैं। उन्होंने पाया कि कुछ सब्जी विक्रेता कुछ सब्जियों को रंग रहे हैं ताकि वे ताजा दिखाई दें।

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सब्जी की दुकानों के निरीक्षण कार्य को तेज किया है। जुलाई, 1995 में तीन नमूनों को अपमिश्रित पाया गया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। विभाग ऐसे विक्रेताओं पर निरन्तर निगरानी रख रहा है।

देश में निर्यात आयात जोन

*15. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्यात-आयात जोनों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;